भारतीय अर्थव्यवस्था में जनांकिकीय लाभांश

डॉ० मन्जू मगन
अर्थशास्त्र विभाग, वी.वी.(पी.जी.) कॉलेज, शामली (उ.प्र.)

सारांश

विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या विकराल एवं भयावह होती जा रही है। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए भार न होकर आर्थिक विकास की सारथी बन सकती है, यदि समय रहते कार्यशील जनसंख्या को सही तरह से उत्पादकता के क्षेत्र से जोड़ दिया जाये। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पूजी गहन औद्योगिक ढांचे पर जोर दिया गया है। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को उतना महत्व नहीं दिया गया, जितनी आवश्यकता थी। ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर और शिल्प उद्योग बन्द पड़े हैं जिन्हे संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। निरन्तर कृषि आय का घटता हुआ स्तर देश के ग्रामीण क्षेत्रों की दयनीय दशा का सूचक है। ऐसी परिस्थितियों में जनांकिकीय लाभांश किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेगा? यह बहुत बड़ा प्रष्न है। शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति अधिक दयनीय है अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करते हुए उच्च शिक्षा में केवल उतने ही युवाओ को प्रवेश दिया जाये जितने की अर्थव्यवस्था में लाभांश वृद्वि के लिए आवश्यक है। भारत की कार्यशील जनसंख्या में बड़ा भाग महिलाओं का भी है अतः महिलाओं को रोजगारन्मुख प्रशिक्षण उनकी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार निर्धारित कर दिया जाये।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः
डॉ० मन्जू मगन

भारतीय अर्थव्यवस्था में जनांकिकीय लाभांश

शोध मंथन, मार्च 2018,
पेज सं0 16–21

Article No. 3
http://anubooks.com
?page_id=581

शोध पत्र में प्रयुक्त अवधारणायें

1. जनांकिकीय लाभ : जब देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का भाग अधिक हो, तो इसे जनांकिकीय लाभ कहते हैं।
2. निर्भर जनसंख्या : निर्भर जनसंख्या वह है जो देश के लिए दायित्व होती है। 0–14 आयु वर्ग व 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वर्ग को जनसंख्या को निर्भर जनसंख्या कहते
3. शिक्षित श्रमिकः शिक्षित श्रमिक से आशय ऐसे श्रमिक से है जिनकी शिक्षा का स्तर सेकेण्डरी या उससे अधिक है।

विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या विकराल एवं भयावह होती जा रही है। विकसित देशों में यद्यपि जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं है, तथापि वहां भी क्षेत्रीय असमानता को स्थिरता प्रदान करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जबकि भारत में आर्थिक विकास का विचार आज महत्वपूर्ण चिन्तन का विषय बना हुआ है। आर्थिक विकास का अर्थ है । अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर बढ़ाना। विस्तृत अर्थ में आर्थिक विकास से अभिप्राय राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके निर्धनता को दूर करना है तथा सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना है। भारत में बढती हुई जनसंख्या से समाज पर आर्थिक भार बढ़ गया है और ऐसी दशायें उत्पन्न हुई हैं जो आर्थिक विकास के लिए प्रेरक नहीं हैं।

शोध पत्र की प्रासगिकताः भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़े जनसंख्या का आयु वर्ग में वितरण आर्थिक विकास के पक्ष में वितरण करते हैं। भारत में 1971 में निर्भरता अनुपात 0.9 था जोकि 2011 में और भी कम होकर 0.6 रह गया है। अतः प्रस्तुत शोध इस अर्थ में प्रासांगिक है कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए भार न होकर आर्थिक विकास की सारथी बन सकती है, यदि समय रहते कार्यशील जनसंख्या को सही तरह से उत्पादकता के क्षेत्र से जोड़ दिया जाये। कार्यशील जनसंख्या के लिए उपयुक्त अवसरों की तलाश कर उन्हें देने सम्बंधी सुझावों के संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र निश्चय ही प्रासंगिक है।

परिकल्पनायें

1. भारतीय जनसंख्या के आंकड़े भविष्य में आर्थिक वृद्धि के सूचक हैं।
2. महिलाओं में बेरोजगारी की दर पुरूषों से अधिक है।
3. अशिक्षित वर्ग में बरोजगारी शिक्षित वर्ग की तुलना में कम है। अतः उच्च शिक्षा को रोजगार से जोडने के लिए कौशल विकास एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के पूर्वानुमान आवश्यक है।

भारत में जनसंख्या के परिमाणात्मक पहलू

भारत का भू– क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व का लगभग 2.4 प्रतिशत है किन्तु उसे विश्व की कुल जनसंख्या के 16.7 प्रतिशत भाग का पालन–पोषण करना पड़ता है। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में जनसंख्या सम्बंधी विभिन्न तथ्य तालिका 1 में देखे जा सकते हैंः–

तालिक संख्या :1

भारत में जनसंख्या

जनगणना वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	दशक में वृद्धि की दर (प्रतिशत में)
1901	23.84	–
1951	36.11	+ 13.31
1961	43.92	+ 21.51
1971	54.82	+ 24.80
1981	68.33	+ 24.66
1991	84.64	+ 23.86
2001	102.87	+ 21.54
2011	121.01	+ 17.64

स्रोत : Census of India, 2011

तालिका : 1 से स्पष्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ है। 1901 की जनगणना के अनुसार उस वर्ष देश की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी। इस प्रकार 110 वर्ष की अवधि में देश की जनसंख्या में 97 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है। किन्तु उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गयी है, जिससे भारत में दो करोड़ की आबादी बढने से रोक ली गई है।

भारत में जनसंख्या का आयु वर्ग में विभाजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश की श्रम शक्ति के आकार के संदर्भ में ज्ञान होता है। 0–14 आयु वर्ग तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को निर्भर जनसंख्या कहते है तथा 15–60 आयु वर्ग के बीच की जनसख्या को कार्यशील या कार्यकारी जनसंख्या कहते हैं। निर्भर जनसंख्या को कार्यकारी जनसंख्या से भाग देने पर हमें निर्भरता अनुपात मालूम हो जाता है। तालिका संख्या 2 से भारत में आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का वितरण देखा जा सकता है।

तालिका संख्या 2

भारत में आयुवर्ग के अनुसार जनसंख्या का प्रतिषत वितरण

आयु वर्ग	2001	2011	2026 (अनुमानित)
0–14	35.4	29	23.4
15.–60	57.7	64	64.2
+60	6.9	7	12.4
	100	100	100

स्रोत : Census of India, 2011

भारत में 1971 में निर्भरता अनुपात 0.9 था, वह कम होकर 0.8 तथा 2001 में 0.73 रह गया । 2011 में इससे भी कम होकर 0.6 रह गया है। निर्भर जनसंख्या किसी भी देश के लिए दायित्व होती है, जबकि कार्यकारी जनसंख्या देश के उत्पादन में मानव संसाधन के रूप में भूमिका निभाती है। अतः किसी देश में कम होती निर्भरता – अनुपात आर्थिक – विकास के लिए अनुकूल मानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यकारी जनसंख्या 69 करोड़ है, जो विश्व में सबसे अधिक है। ऐसा अनुमान है कि अगले 50 वर्षों तक यह कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात अधिक ही रहेगा।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार आर्थिक नियोजन किया जाये, जिससे कार्यकारी जनसंख्या 69 करोड़ का उत्पादक कार्यों में पूर्ण योगदान हो सके। भारत में बेरोजगारी का इतिहास अत्यन्त भयानक है। भारत सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी यह समस्या स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी ज्यों की त्यो खड़ी है। यदि भारतीय बेरोजगारी में युवाओं (15–29 वर्षों) को देखा जाये तो 1993–94 से 2015–16 की अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में ही बेरोजगारी दरों में वृद्धि हुई है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र आर्थिक समृद्धि में बाधक है। (तालिका संख्या 3)

तालिका संख्या 3

रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013–14 पर आधारित भारत में बेरोजगारी की दरें (प्रतिशत में)

	ग्रामीण			नगरीय			कुल अखिल	
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
सामान्य प्रधान प्रस्थिति के अनुसार (UPS)	4.2	6.4	4.7	3.9	12.4	5.5	4.1	7.7
सामान्य प्रधान एवं सहायक प्रस्थिति (UPSS)	2.7	3.41	2.9	3.5	10.8	4.9	2.9	4.9

स्रोत : बेरोजगारी रिपोर्ट 2013–14, श्रम ब्यूरो, शिमला

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य प्रमुख प्रस्थिति के आधार पर 2013–14 अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर 4.9 प्रतिशत थी। ग्रामीणी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर 4.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रो में 5.5 प्रतिशत थी। पुरूषों की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी दर ग्रामीण व शहरी दोनो क्षेत्रों में ही अधिक है।

बेरोजगारी का दुःखदायी पहलू यह है कि भारत में शिक्षितों की संख्या में वृद्धि दर बेरोजगारी की दर में वृद्धि दर से अधिक है। उदाहरणार्थ : वर्ष 2004–05 में शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी की दर 15.6 थी । जबकि अखिल भारतीय बेराजगारी दर 6.9 प्रतिशत थी। इस प्रकार कुल बेरोजगारी की दर शिक्षित बेरोजगारी की दर से लगभग तीन गुना कम थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी भयावह है क्योंकि वर्ष 2004 –05 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी की दर 15.2 प्रतिशत थी जबकि भारत

के लिए यही अंक 1.8 प्रतिशत था। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षित रोजगार के अवसरों में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। (तालिका संख्या 4)

तलिका सख्या –4
षिक्षा के स्तर के अनुसार बेरोजगारी दर (वर्ष 2015–16) श्रम बल के प्रतिषत के रूप में

कारण	स्नातक			परास्नातक		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण शहरी
शिक्षा के अनुरूप रोजगार न होना	55.9	64.0	58.3	58.5	68.7	62.4
उचित पारितोषक न प्राप्त होना	25.1	17.5	22.8	24.8	16.0	21.5
पारिवारिक कारण	5.5	5.0	5.4	3.7	4.0	3.8
अन्य	13.5	13.5	13.5	13.0	11.3	12.4

स्रोत :– पॉचवा वार्षिक रोजगार –बेरोजगार सर्वेक्षण 2015–16, रोजगार एंव श्रम मंत्रालय चंडीगढ़

तलिका संख्या 4 से स्पष्ट है कि लगभग 58.13 प्रतिशत स्नातक जनसख्या को शिक्षा के अनुरूप रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा एवं 22.8 प्रतिशत लोगों को उतना पारिश्रमिक नहीं मिल रहा, जितने के वे योग्य हैं। परास्नातक जनसंख्या के आंकडें तो और भी भयानक है। 64.4 प्रतिशत परास्नातक उपाधि वाले व्यक्तियों को शिक्षा के अनुरूप रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने में उनके जीवन के बहुमूल्य दो वर्ष बिना उत्पादकता के व्यर्थ हुए है।

तेजी से उभरती नई तकनीकी के कारण भारत में रोजगार का परिदृश्य बदल रहा है। फिक्की, नैककाम और ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माण व सेवा के संगाठित क्षेत्र में वर्तमान में 3.8 करोड़ व्यक्ति कार्यरत हैं। पॉच साल में इनकी संख्या 4.8 करोड़ तक पहुंच जायेगी। नई नौकरियों में 20–25 प्रतिशत योगदान संगठित क्षेत्र करेगा। इससे अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो जायेगी। अगले पॉच साल अर्थात् 2022 तक 9 प्रतिशत लोग ऐसी नौकरियां कर रहे होगें जो आज अस्तित्व में ही नहीं हैं। 37 प्रतिशत लोगो को नई स्किल सीखने की आवश्यकता होगी , जबकि 21 प्रतिशत लोगों की नौकरी जाने का खतरा हो सकता है। यह अनुमान उद्योग संगठन एसोचैम, आई टी उद्योग के शीर्ष संगठन नैसकॉम और पेशेवर सेवायं देने वाली मल्टी नेशनल फर्म ईवाई की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है। इनके अनुसार देश में वर्ष 2022 में 60 करोड़ लोगों की वर्ककोर्स होगी।1

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्यौगिक विकास के बाद आज भी भारत के 48 प्रतिशात व्यक्ति कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों पर निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्वि दर उंची होने के बाद भी ग्रामीण जनता के लिए नये रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा। एक ओर ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी ओर शहरों की ओर ग्रामीण जनसंख्या का पलायन भी बढ़ कर शहरीकरण की समस्याओं को तेजी से बढ़ा रहा है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पूंजी गहन औद्योगिक ढांचे पर जोर दिया गया है। लघु एंव ग्रामीण उद्योगों को उतना महत्व नहीं दिया गया, जितनी आवश्यकता थी। ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर और शिल्प उद्योग बन्द पड़े हैं जिन्हें संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। निरन्तर कृषि आय का घटता हुआ स्तर देश के ग्रामीण क्षेत्रों की दयनीय दशा का सूचक है। ऐसी परिस्थितियों में जनांकिकीय लाभांश किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति अधिक दयनीय है। देश के 62.4 प्रतिशत लोगों का परास्नातक की डिग्री से कोई लाभ नहीं हो रहा, वे उत्पादकता की दृष्टि से देश को व स्वयं को कुछ नहीं दे पा रहे, तो ऐसी डिग्रियां बांटने को लाभ नहीं है, अपितु देश के सकल घरेलू उत्पाद में हानि है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करते हुए पहले यह अनुमान लगाया जाये कि स्नातक व परास्नातक डिग्रियों सें देश को कितना जनांकिकीय लाभ मिलने वाला है। शिक्षा एंव प्रशिक्षण को रोजगार की कुंजी माना जाता है। किन्तु भारत में उच्च शिक्षा के बावजूद लोग बेरोजगार हैं। अतः उच्च शिक्षा में केवल उतने ही युवाओं को प्रवेश दिया जाये जितनों की अर्थव्यवस्था में लाभांश वृद्वि के लिए आवश्यकता है। उत्पादन के क्षेत्र में अब तक विदेशों की नकल करते हुए पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाया गया है जिसे श्रम संचालित तकनीक में बदलने की आवश्यकता है। युवाओं को शारीरिक श्रम की ओर आकर्षित करने के लिए श्रम प्रधान उत्पादक कार्यों में ऊंची पारिश्रमिक की न्यूनतम दरें सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र में भी प्रतिव्यक्ति आय में वृद्वि संभव हो सके । भारत की कार्यशील जनसंख्या में बड़ा भाग महिलाओं का भी है अतः महिलाओं को रोजगारन्मुख प्रशिक्षण उनकी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार निर्धारित कर दिया जाये। महिलाओं के लिए आंशिक रोजगार व्यवस्था (4–5 घटें काम) काम अधिक न्यायोचित्त लगता है। अतः उनका कौशल विकास कर कार्य के कम घन्टे निर्धारित करके जनांकिकीय लाभांश में उनकी भागदारी को बढाया जा सकता है

1. दैनिक भास्कर, 15 दिसम्बर 2017,पानीपत पी.8 (बिज़नेस)

संदर्भ स्रोत

- अमृत्य सेन,1973 *´Poverty, Inoquality, unemployment, some conceptual in Measurement*, "Economic & Political weekly.
- प्रसाद, एल **2008** *´´आधुनिक भारत अर्चना´´* पब्लिकेशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली
- मिश्रग्रीस , **2012** आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास ग्रंथ शिल्पी प्रा0 लि0 , नई दिल्ली
- राजकृष्णा *´Unemployment in India´´*, EPW March, **1973**
- सेन सुकोमल, **2012**, *´´भारत का मजदूर वर्ग´´*, नई दिल्ली